Clause 3 was added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री धर्मेंद्र प्रधानः महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि विधेयक को पारित किया जाए।

The question was put and the motion was adopted.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, we will take up another Bill. माननीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं आपको निजी टिप्पणी के लिए धन्यवाद देता हूँ। The Repealing and Amending Bill, 2023. Shri Arjun Ram Meghwalji to move a motion for consideration of the Repealing and Amending Bill, 2023.

The Repealing and Amending Bill, 2023

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CULTURE (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Sir, with your permission, I move:

"That the Bill to repeal certain enactments and to amend an enactment, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration. "

श्री उपसभापतिः माननीय मंत्री जी, क्या आप इस पर कुछ बोलना चाहेंगे?

श्री अर्जुन राम मेघवालः जी, सर। मैं इस पर कुछ बोलना चाहूँगा।

श्री उपसभापतिः बोलिए।

श्री अर्जुन राम मेघवालः सर, नरेन्द्र मोदी जी के शासन में आने के बाद लगातार ऐसे एक्ट्स, जिनकी कोई उपयोगिता नहीं थी, उनको समाप्त करने की एक प्रक्रिया चली।

4.00 **P.M.**

वह प्रक्रिया तेजी से चली और अब तक हम ऐसे 1,486 एक्ट्स निरस्त कर चुके हैं। अभी 1965 का एक बिल था, उसके बाद ऐसे 11 एक्ट्स ऐड हुए। मैं जो बिल लेकर के आया हूं, उसमें ऐसे टोटल

76 एक्ट्स हैं, जिनको निरस्त करने के लिए हमने आप सबके बीच, इस महान सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

इनमें से कुछ आज़ादी से पहले के भी हैं और कुछ आज़ादी के बाद के भी हैं, तो ऐसे टोटल 76 एक्ट्स हैं, जिन्हें समाप्त करने का यह बिल है। मैं यहाँ उनमें से एक-दो के उदाहरण देने की कोशिश करूंगा। जैसे, The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 है। किसी जमाने में टेलीग्राफ बहुत महत्वपूर्ण होता था, उसकी वायर आप रख नहीं सकते। अगर आप उसे रखोगे तो वह एक unlawful activity होगी, आपको दंड मिलेगा। ऐसे एक्ट की अब कहां जरूरत है? हम ऐसे ही एक्ट्स समाप्त करने के लिए आपके इस महान सदन के बीच में आए हैं। प्रधान मंत्री जी ने जो 'पंच प्राण' कहा है, उनमें से एक प्राण गुलामी के अंशों से मुक्ति भी है। ये एक्ट्स pre-colonial period के हैं, pre-Constitution period के हैं, तो ये गुलामी के अंश भी हैं, तो उनसे भी मुक्ति मिलती है।

महोदय, चूंकि आप एक कवि हैं, इसलिए मुझे याद आ गया कि किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है:-

"अगर आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जा,
ठहरा पानी थक जाता है, वह तो अपनी काई से।"

अगर इस ease of living system में कोई ऐसा एक्ट है, जो नागरिकों के लिए भी आवश्यक नहीं है और परेशान करने वाला है, तो उसको समाप्त करना ही उचित है। जैसा मैंने कहा, The Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act, 1950 है, इसकी अब कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा किसी ने नहीं सोचा। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जो ऐसे कानूनों को निरस्त करने के लिए निरंतर सोच रही है और नागरिकों को ease of living प्रदान कर रही है, इसलिए चर्चा करके या सर्वसम्मति से इसको पास करें, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

The question was proposed.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Dr. L. Hanumanthaiah. He is not present. Shri G.V.L. Narasimha Rao.

SHRI G.V.L. NARASIMHA RAO (Uttar Pradesh): Mr. Deputy Chairman, Sir, this Bill is in continuation of a series of pro-governance measures initiated by hon. Prime Minister ever since he became Prime Minister in May, 2014. As soon as he took over the reins of office, a two-member committee was constituted to identify all Acts that have no relevance in today's context. And, so far, 1,486 such Acts have been taken off from the statute book. So, this is a massive cleanup exercise. This was done to ensure that primitive and irrelevant Acts do not form part of the statute book.

Sir, in the present Bill, we are, actually, seeking to repeal 76 such Central Acts which have no relevance or do not need to exist in the statute book. Sir, 229 State Acts have already been found to be irrelevant in today's context and have actually been recommended to the State Governments for repeal. But, in this context, I would like to say, not just repealing Acts, hon. Prime Minister, Modiji, has taken a number of reformative measures to ensure cleaner governance. "जनता के ऊपर मेरा विश्वास है," यह कहते हुए माननीय प्रधान मंत्री जी ने self-certification authentication को लागू किया। पहले आपको हर सर्टिफिकेट के authentication के लिए किसी गज़ेटेड ऑफिसर के पास जाना पड़ता था। प्रधान मंत्री जी ने ऐसी स्थिति को पूरी तरह से खत्म किया है। यह आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी। इसी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 के बाद क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों के लिए इंटरव्यूज़ को खत्म किया, उसमें जिस प्रकार का discretion रहता था, उसको भी खत्म करने का काम किया है। कुछ ऐसी नौकरियां हैं, जैसे ग्राम डाक सेवक आदि में आपको केवल 10वीं कक्षा के मार्क्स के आधार पर नौकरी मिल जाती है, उसमें किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हर तरह के पोलिटिकल और अन्य तरीके के influence को खत्म करने का काम किया है। हर विषय में एक सुधार हुआ है। पिछले सत्र में हमने एक बिल पारित किया था, जो प्रिंट मीडिया के रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत लम्बी-चौड़ी प्रक्रिया थी। ब्रिटिशकाल में मीडिया पर जो अंकुश रहता था, उस प्रकार के अंकुश का आज कोई relevance नहीं है, उसको खत्म करने का काम किया है। इसी तरह से पिछले सत्र में हमने जन विश्वास बिल के ज़रिये बहुत सारे कानूनों में से क्रिमिनल प्रावधानों को खत्म करने का काम किया है। So, the hon. Prime Minister has fulfilled his commitment of 'Minimum Government, Maximum Governance'. 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के ज़रिये देश की जनता ने माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा इस प्रक्रिया का पूरी तरह समर्थन किया है, जिसका नतीजा आपको हाल के चुनावों में नज़र आया है और भविष्य में भी, वर्ष 2024 के चुनावों के नतीजों में एक भव्य जीत के साथ माननीय प्रधान मंत्री जी को एक बार फिर से देश की सत्ता संभालने का निर्णय देश की जनता कर चुकी है। सर, इसके लिए pro governance और reform सबसे बड़ा कारण है और ease of doing business के साथ-साथ ease of living भी है कि आम नागरिक अपने जीवन में जो कष्ट झेलते हैं, सरकार के द्वारा उनको कैसे खत्म किया जाए, सरकार के द्वारा ease of living को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इस प्रकार सामान्य मानव के जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन लाना प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का एक लक्ष्य रहा है और इस लक्ष्य को अचीव करने में माननीय प्रधान मंत्री जी सफल हुए हैं। यही देश की जनता के आशीर्वाद का प्रमुख कारण है। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Next, Shri Jawhar Sircar, not present; Dr. Kanimozhi NVN Somu, not present; Shri Sushil Kumar Gupta, not present. Shri Muzibulla Khan.

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा): महोदय, the Repealing and Amending Bill, 2023 देश की कानून व्यवस्था मे सुधार लाने और उसे बेहतर बनाने के लिए आम आदमी की सहूलियत के लिए

लाया गया है। महोदय, 65 अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री श्री किरेन रिजिजु जी इसे लोक सभा में लाए थे और वर्तमान में हमारे कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने 11 कानूनों को add करने के बाद 76 कानूनों को निरस्त करने के लिए इस बिल को पेश किया है। 27.07.2023 को लोक सभा में इस विधेयक को पारित कर लिया गया है। इस विधेयक की तीन अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में वर्ष 1850 से वर्ष 2020 के बीच 35 अधिनियम शामिल हैं। दूसरी अनुसूची में वर्ष 2013 से 2017 के बीच 41 विनियोग अधिनियम शामिल हैं, तीसरी अनुसूची में वर्ष 2011 का एक माइनर संशोधन के साथ एक अधिनियम आया हुआ है। यह बिल जीवन जीने और काम करने में आसानी सुनिश्चित करेगा। अप्रचलित अधिनियमों को निरस्त करने के उद्देश्य से यह 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन' के दृष्टिकोण को पूरा करता है। बरसों से जो कुछ जमा हुआ है, उसे ठीक करने के लिए एक बार के प्रयास पर भरोसा करने के बजाय ऐसी स्थिति को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने के लिए भी गति का अवरोध किया जाना चाहिए था। सर, समय-समय पर समीक्षा खंडों को कानून में शामिल किया जाना चाहिए। जैसे-जैसे कानून अधिक specific होते जा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि कानून को संभालने के लिए इस स्थिति के आस-पास की परिस्थितियों को बदला जाना बहुत जरूरी है और इसकी जांच भी बहुत जरूरी है। कानून की समय-समय पर समीक्षा के लिए, समाधानों के लिए effectiveness और समस्याओं की प्रकृति के बारे में चर्चा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार सबूत आधारित तीन निर्णयों को बढ़ावा दिलाना जरूरी है, जो इसके माध्यम से किया जा सकता है। सूर्यास्त खंड international level पर दूसरे देशों में बीस से अधिक वर्षों से sunset clause के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यूरोप के कुछ देशों में कानून का समीक्षा तंत्र है, जिसमें एक निर्दिष्ट तरीके से इंटरवल पर समीक्षा की जाती है। भारत में कहीं भी कोई संस्था नियमित रूप से यह नहीं देखती कि कानून ज़मीनी स्तर पर ठीक से पहुंचता है या नहीं, ठीक से चलता है या नहीं। आम तौर पर concerned Ministry किसी कानून के संपूर्ण या विशिष्ट भागों का मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करती है। कभी-कभी पार्लियामेंटरी कमेटी विधान जांच कराती है, लेकिन यह जांच sufficient नहीं है। हालांकि अधिकांश मामलों में विधान जांच का उपयोग तभी किया जाता है, जब समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि यह जो 76 कानूनों को निरस्त करने प्रस्ताव आया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। उसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी जो कानून है, जिस कानून को लेकर अभी भी समस्या है, क्योंकि मैं बचपन से देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री को गोली मारने के बाद भी न्याय पाने में 27-30 साल लग जाते हैं। उस कानून में भी कोई त्रुटि होगी, तो उस कानून में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि न्याय जितनी जल्दी मिल सके, डिसीज़न जितना जल्दी आ सके, वह हमारे देश के लिए अच्छा होगा। उस इंसान के लिए भी अच्छा होगा, जो कि इसमें victim हुआ हो, वह दोषी है या नहीं है। आठ-दस साल लोग जेल में रहते हैं और दस साल के बाद पता चलता है कि वह निर्दोष है। हमें इस चीज़ को देखना बहुत जरूरी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस चीज़ को आप rectify कीजिए, ताकि जो सरल लोग हैं, वे बेकार में फंस कर रहते हैं, जेल में अपनी जिंदगी काटते हैं, वे लोग जेल से कैसे मुक्ति पाएंगे, इसके बारे में आप जरूर देखिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV (Andhra Pradesh): Sir, I thank you for giving me an opportunity to speak on such an important Bill on behalf of our YSRC Party. We have no objection to this Bill and welcome it wholeheartedly. It is a credit to this Government that they have brought in such widespread changes and sought to alter laws and regulations that have become obsolete.

India is a dynamic nation and our Constitution-makers were aware of this when they laid down the fundamental principles, which would guide our nation; so, they allowed enough flexibility to make changes and ensured that no law could keep the people of India entrenched in the past. The fact that this Government has made concerted efforts to unearth contradictory and obsolete legislations, some of which date back to colonial times, ensures that we honour our roots as a nation open to change and progress.

Additionally, it severs any unnecessary ties to outdated draconian laws from the era of British rule and usher our country into a new era of liberation where we actualize our dreams of becoming 'vishwa-guru'

Sir, I would now like to make some suggestions. First, I would like to give some suggestions on the AP Reorganization Act. While I wholeheartedly support the breath of the changes being made through this Bill, I would also like to highlight that Andhra Pradesh had requested for an Amendment to the Andhra Pradesh Reorganization Act, 2014. This has been brought to the attention of this House through multiple interventions, including Private Member's Bills, and, through the Government, more directly through personal representation from hon. MPs and State leaders of Andhra Pradesh.

Sir, we had requested that the promises made under the AP Reorganization Act be actualized in a time-bound manner but there are several matters which till date have no end in sight. This includes the Central Tribal University promised to Andhra Pradesh Government which only began functioning in 2019 from a temporary campus. There is no clarity on when a permanent campus will be provided.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Masthan Raoji, please speak on the subject.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: Sir, some amendment to the Reorganization Act is required. This is our humble request.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: It is good.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: Similarly, we request that Special Category status be provided to the State. Such a status would enable us to get a higher share in Central grants and tax incentives resulting in the reduction of financial burden on the A.P. Government. It is required by A.P. because we have been fiscally struggling due to an unscientific bifurcation wherein amongst numerous resources, we lost our capital city also. Even the 15th Finance Commission has stated that giving such a status is within the mandate of the Centre to provide if it deems it necessary. I request that in face of the new changes being brought by the Government, this too be given due weightage. Additionally, the funds promised to AP for development projects should be handed over to our Government in a smooth and efficient manner. Till date, many projects, such as Polavaram Irrigation Project, are stuck halfway due to disputes over funding. This disrupts the intent and nature of the law which was meant to provide developmental support to the Telugu people. I request that these stipulations be reconsidered and the commitments made to us be legally strengthened.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please conclude. Beedha Rao Masthanji, you know the rules. You have to speak on this Bill. You have to speak on this Bill as per rules.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: Yes, Sir, I am coming to that.

Sir, there are a few laws which too need amendment because they are simply baffling and highly outdated considering our times. I would like to highlight the following points. As per the Indian Aircraft Act, 1934, any Indian citizen who flies balloons or kites without license is an offender. The House is well aware that flying kites is a common method of celebration and a strong part of the Indian cultural ethos, especially, for children. While this is not usually implemented, it is time this stipulation be removed. Sir, the Indian Treasure-trove Act of 1878 states that any 'treasure' found under the soil which is equal to or more than Rs 10 has to be reported and shared with the Government. If any person does not do so, they are liable to be arrested. This is vague and extremely confusing for the general public, and this can easily be misused by mischief-makers to persecute innocent citizens. On a graver note, there are pressing laws that need urgent reform so as to prevent serious miscarriages of justice. This includes the Indian Penal Code and several laws pertaining to the treatment of criminal. ...*(Time-bell rings.)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please. Your time is over. ...*(Time-bell rings.)*...

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: For example, as per Section 294 of the Indian Penal Code, anyone who acts in an obscene manner in a public place is punishable. ...(*Time-bell rings.*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Beedha Masthan Raoji, your time is over. Please.

SHRI BEEDHA MASTHAN RAO YADAV: In conclusion, Sir, I would say that I have already stated that I wholeheartedly, on behalf of the YSR Party, support the proposed Bill. Through my speech, I merely wished to point out certain inconsistencies, which cannot be allowed to remain in the current climate. It should be done to further the good work of this Government.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri K.R. Suresh Reddyji.

SHRI K.R. SURESH REDDY (Telangana): Sir, thank you for giving me this opportunity to speak on this Bill which, though considered a normal and routine Bill, has got a lot of significance. The hon. Minister, in the explanation of the Bill, has very rightly stated that some of the Bills, which are outdated, antiquated and have lost their relevance, need to be repealed and withdrawn. This, definitely, is a good measure. It is a measure which can lessen the burden on the judiciary; it is a measure which can sharpen the bureaucracy and ultimately help the people, at large. So, any initiative in this regard is always welcome and getting updated is a very good initiative, especially today, and more so in the international forums. Having said that and having appreciated their initiative, you have to see the other side of the coin too. When a Bill is passed, the Bill gets effective only after the rules are made. There are so many Bills which have been passed, but the rules are pending. The subordinate legislation goes through all this. The other day, we had a presentation of so many reports, stating very clearly that the Bills have been passed, but the rules are not being framed and they have been delayed for a considerable period of time. Now, the onus lies on the hon. Parliamentary Affairs Minister to look in this direction. While the Government is reforming, the Parliament also needs to rise to the occasion and the Parliament has a bounden duty to realise its realism because the laws are made here. So, subordinate legislation is one area which needs your attention.

Another most important aspect of any legislation is, how you analyse the impact of it, which is known as Legislative Impact Assessment. There are two ways of looking at it. One is, before the Bill is introduced, the Government, definitely, puts it up in the public domain for its inputs. There is a policy in 2004 which has been

framed, but there is no law which mandates the Government that any Bill proposed should be put in the public domain. To quote a small example, from 2016 to 2019, there were almost 186 Bills introduced and out of which 142 Bills did not get public scrutiny before coming here. That is very glaring. In such a big democracy, where public input is not taken before the introduction of the Bill, it creates, I would say, a lot of uneasiness among the people and also trouble to the Government. After the Bill is introduced and passed, how effective is the Bill? Is there any impact assessment mechanism? World over, most of the developed countries do have this mechanism. They evaluate how beneficial a Bill is to the people. If there are certain amendments to be made, then, the Government can come in through those necessary changes. One good example of that impact assessment not done and the damage being done to the society, at large, and the Government, in particular, was Farm Bills. The Farm Bills were introduced, but the impact assessment was not done. We went through a huge turn up. People died and, ultimately, the Government had to go back on them. This is one area where the legislature, and more so from the Chair side, need to get a little more dynamic in this and ensure that the Parliament lives up to its bestowed responsibilities.

Finally, the last thing is the international treaties. There are so many international treaties that the Government is signing. While we have removed a lot of outdated Bills, there are certain treaties which come in. For example, the Antarctic Bill came in. The treaty was signed 40 years ago and we have come with the Bill now. The Government should realise that it is coming to this House after 20 or 30 years, when the relevance is lost. While welcoming the removal of the outdated Bills, I also seek the hon. Minister's intervention in this regard... ...(*Interruptions*)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Your allotted time is over.

SHRI K.R. SURESH REDDY: If my time is over, I respect the Chair and conclude.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: If you want to conclude, please do it.

SHRI K.R. SURESH REDDY: I was just saying that we are a representative democracy, and if the suggestions made by most of us here are heeded to, then, you turn into a responsible democracy. That is what the country needs today. Dynamism does not mean just removing outdated Bills, but dynamism means that you bring in legislation which is beneficial to the people, and also before legislation and after

legislation, you should involve the people. So, that is how the Bills, in letter and spirit, would be appreciated. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri A.A. Rahim - not present. Dr. M. Thambidurai.

DR. M. THAMBIDURAI (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Deputy Chairman, Sir. I am participating in this discussion on behalf of the AIADMK Party. The hon. Minister has brought the Repealing and Amending Bill, 2023. Since 1950, there have been various Repealing and Amending Acts. Sir, 1,370 Acts were repealed from 1950 to 2001. There have been two Repealing and Amending Acts in 2015 and 2016. The latest Act is the Repealing and Amending Act, 2019. The Act is a periodic measure taken by the legislature to repeal the laws which are obsolete and ineffective. As we know, most of these Acts were enacted during the British period. Though we generally refer to the Indian Constitution, but some of the Acts enacted by the British are still in force. There may be some old laws. Other countries also have some old laws, but repealing is done because some of the old laws are not necessary, and those old laws can be used to harass the people. Therefore, what is the necessity of keeping those kinds of Acts?

Then, I want to bring a very important issue to the notice of the hon. Minister. Around 65,000 cases are pending in the Supreme Court. About 4.5 million cases are pending in the High Courts. In the lower courts, about 26 million cases are pending. So many cases are still pending in different courts. Therefore, when we have so many laws, it becomes very difficult to overcome the problem of huge pendency of cases and the problems faced by the litigants. As the hon. Member said, the laws are meant for the general public and for benefiting the democracy. In a democratic spirit, if we bring a new law, that must be useful to the people. If at all a law is not proving to be useful for the people, there is no meaning in having that law. Therefore, in that sense, if the hon. Minister has brought this kind of a Bill for repealing the old laws, I hope that will be for the benefit of the people. Even in case of some of the old laws that we are repealing today, if at all any relevance is there in those laws also, that has to be modified and kept for the public benefit. We cannot remove all the laws simply for the reason that the British brought those laws. That is my suggestion. Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Shri Mahesh Jethmalani. You have three minutes.

SHRI MAHESH JETHMALANI (Nominated): Sir, this Bill is a formal Bill. It is, basically, a case of legal house cleaning. Our legal godown had become over full with

laws which are obsolete, some of which were pointed out by the previous speakers and the Law Minister in particular. So, there was a need for some legal house cleaning, particularly since the previous Government had not undertaken this task and left many obsolete laws. So, the work of this Government ever since 2014 has been in that direction and, of course, it is unlike empty slogans like '*garibi hatao*'. It is towards the policy of 'न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन'। It is an exercise in that direction and an exercise essentially, as I said, for cleaning our legal godowns. It is a short Bill but there are three categories. From these three categories which are set out in three different schedules, one will be able to discern as to what is the nature of the laws, which are being got rid of. In the First Schedule, there are laws which are basically obsolete and they are being repealed altogether, as the hon. Law Minister pointed out. For instance, there are laws which have been overtaken by technological advancement. Such is the Telegraph Wires (Unlawful Possession) Act. It is now almost obsolete since nobody uses such communication anymore. We are in the age of spectrum now which has made this law obsolete. Many of the colonial laws, which date back to 1850 or 1855 and so on, have been removed from the statute books. Then, there are laws which are amendment laws. If you see, half of the first Schedule consists of amending laws. These are amendments to existing statutes. These are Amending Acts and these amendments have now been incorporated into the parent Acts, and, they have become completely useless now, and, they have no purpose still being on statute books. They only over-burden our legal godowns and our statute books.

Sir, the Second Schedule, if you see, is entirely for Appropriation Bills for a particular year. You have an Appropriation Bill for 2013, 2014, 2015, 2016. These Bills have time limits and they are only for a particular year. They have outlived their purpose and their shelf life is over but, unnecessarily, they are still on our statute books. So, these laws also have to go. This is the second category.

Last category is a single case. If it was a case of amendment or a serious amendment to any Act, then, it would be discussed and debated in both the Houses but it is a formal amendment. One word has been dropped in a particular statute, which is the Factoring Regulation Act. There is an amendment Act of very minor consequence. It is more of a grammatical change and that is why the Third Schedule is there, which consists of an amendment to only one Act, the Factoring Regulation Act.

We have a policy of Minimum Government, Maximum Governance and this is an act to further that objective and it is an act to further the absence of harassment to

ordinary citizens, particularly, the poor; and to enhance the Ease of Living and Ease of Doing Business for businessmen and such categories.

In the end, I whole-heartedly welcome the Bill. It is a necessary Bill, formal though it is. At least, Sir, it is an exercise in much-needed legal housekeeping. I thank you and my Party for giving me the opportunity to speak on the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri Raghav Chadha, not present; Dr. Fauzia Khan, not present; Shri Naresh Bansal. You have three minutes.

श्री नरेश बंसल (उत्तराखंड): उपसभापति महोदय, मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का आदेश दिया है। हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जब से देश में सरकार आई है - 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन', इसको लेकर जो आजादी के पहले से गुलामी की मानसिकता की चीज़ें थीं, उनको हटाने का अभियान चला। समाज में सब प्रकार से स्वच्छता अभियान चलाने का काम प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ और हर क्षेत्र में उसका परिणाम भी देखने को मिला। यह केवल झाड़ू वाली स्वच्छता ही नहीं है - अनेक प्रकार से, जैसे आज का जो विषय है, रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल, 2023, जिसमें बहुत सारे कानूनों को, जो एक प्रकार से हमारी जनता के ऊपर भार थे, समाप्त करने का काम सरकार प्रारंभ से ही कर रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे, वे इसलिए बनाए थे कि वे हम पर शासन कर सकें, हमको प्रताड़ित कर सकें। वे कोई सुधार के लिए नहीं थे, बल्कि अपने शासन को मजबूत करने के लिए थे।

आजादी के बाद वे कानून समाप्त होने चाहिए थे, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी ने हर क्षेत्र में जो पुराने-पुराने बर्डन्स थे, उनको समाप्त करने का काम किया। उन्होंने 40 साल की 'वन रैंक, वन पेंशन' को सॉल्व किया। इसी प्रकार से उन्होंने 34 साल के बाद हमारी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया, जिससे आने वाली पीढ़ी देश के स्वाभिमान की आवश्यकता के अनुसार देश के शासन में सहयोग कर सके। इसी प्रकार से कानून के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत से कानून थे, ऐसे लगभग 1,486 कानून थे, जिनको एक दो सदस्यीय कमीशन की रिकमंडेशन पर निरस्त किया गया, क्योंकि वे हमारे ऊपर एक भार थे। बहुत सारे कानूनों की आवश्यकता ही नहीं थी, लेकिन वे कानून की किताबों में भी बोझ थे, हमारे जजेज़ के ऊपर भी बोझ थे, हमारे वकीलों के ऊपर भी बोझ थे और हमारी जनता के ऊपर भी बोझ थे। उनको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। उसी प्रकार से हमारी सरकार ने 2014 में जो दो सदस्यीय समिति का गठन किया था, उसके आधार पर 1,458 अधिनियमों को इसी प्रकार से निरसित कर दिया और संबंधित मंत्रालयों द्वारा निरसन के लिए जो 28 संशोधन अधिनियम छाँटे गए, उनको भी निरसित किया। इस प्रकार 1,486 अधिनियमों को निरसित किया गया।

माननीय उपसभापति जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से ऊपर कहा गया, अधिनियमों को निरसित करने के लिए अभ्यास का उद्देश्य नागरिकों के लिए अनुपालन के बोझ को कम करना और आम आदमी को सुविधा प्रदान करना है। सभी क्षेत्रों में, जिस प्रकार से ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में अनेक प्रकार के कानूनों को निरस्त करके हम जीएसटी लेकर आए, जिसमें 17

कानूनों को 'वन नेशन, वन टैक्स' करके सम्मिलित किया गया तथा लोगों को व्यापार में और टैक्स देने में सुविधा प्रदान की गई, इसी प्रकार से हमने ईज़ ऑफ लिविंग में भी बहुत सारे सुधार के काम किए हैं। उसी को आगे रखते हुए हम इस प्रकार से आज यह बिल लेकर आए हैं। हमारे माननीय कानून मंत्री जी जो बिल लेकर आए हैं, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि यह बिल उन 229 राज्य अधिनियमों को, जिनको निरस्त करने के लिए राज्यों को भेजा गया था, संबंधित राज्य सरकारों ने अब तक उनमें से 79 को निरस्त कर दिया है और जिन 65 कानूनों/अधिनियमों को निरसित करने के लिए आज यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है, इसमें 11 कानून और जोड़े गए हैं, जो स्वतंत्रता से पूर्व के थे, जिनके कारण आम आदमी को बहुत असुविधा होती थी। वे कानून आम आदमी के मतलब के नहीं थे, कानून की किताबों में वे केवल बोझ के रूप में पड़े हुए थे। आम आदमी को उनसे परेशानी होती थी, हमारे जजेज़ भी उनके दबाव में रहते थे, हमारे वकील भी उनके दबाव में रहते थे और जनता को उनसे किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी। जनता के लिए भी वे एक प्रकार से हर्डल्स थे। लोक सभा में 27.7.2023 को इसके लिए 76 अधिनियमों के लिए जो बिल लाया गया था, जो वहाँ पर पास हुआ है, उसी को आज यहाँ पर लाया गया है।

(**सभापति महोदय** *पीठासीन हुए।*)

माननीय सभापति जी, हमारी सरकार 'न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन', इसके लिए जानी जाती है। हर क्षेत्र में कम से कम सरकारी हस्तक्षेप हो और हर आदमी को सुविधाजनक रूप से देश के नागरिक के रूप में, कर्तव्यवान नागरिक के रूप में अपना दायित्व निर्वहन करने का मौका मिले, इसके लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। ...(**समय की घंटी**)... हमने इसी प्रकार से यह देखा कि देश के अंदर विदेशों से फंडिंग वाले ... सर, क्या मैं बैठ जाऊँ?

श्री सभापतिः नहीं, आप कन्क्लूड करिए, आप बैठिए मत। You are making very good points. आप कन्क्लूड करिए।

श्री नरेश बंसलः सर, मैं कन्क्लूड कर रहा हूँ। हमने देखा कि विदेशों से फंडिंग वाले ऐसे अनेक एनजीओज़ थे, जो देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ जुड़े रहते थे। महोदय, ऐसे लगभग 20,000 NGOs निरस्त किये गये। करीब 2 लाख shell companies, जिनके माध्यम से money laundering का काम होता था, काले धन को सफेद करने का काम होता था, उनको निरस्त किया गया। इस प्रकार से हर क्षेत्र में सुधार करने का काम हमारे यशस्वी नेता नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है।

महोदय, अभी पिछले ही दिनों हमने देखा कि किस प्रकार से अंग्रेजों के बनाये हुए पुलिस एक्ट, Criminal Procedure Code और Evidence Act को निरस्त करके अपने नागरिकों के स्वाभिमान के अनुसार नया कानून बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। इस तरह से देश के ऊपर इस प्रकार के जो भी भारस्वरूप या अनुपयोगी कानून थे या जिस क्षेत्र में भी अनुपयुक्त थे या

हैं, उनको समाप्त करके, हम संकल्पबद्ध हैं कि हम भारत देश को अगले 25 वर्षों में एक विकसित राष्ट्र बनाएँगे। उसके लिए हम इस प्रकार के सारे सुधारात्मक कदम उठाने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ। आपको धन्यवाद, नमस्कार।

MR. CHAIRMAN: Shri P. Wilson. You have five minutes.

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I will speak on the Repealing and Amending Bill. It is better to have a sunset clause in all the Bills. Whenever you introduce a Bill, it should have a sunset clause. Once a Bill is introduced and passed, it becomes an Act. But because of sunset clause, the Bill becomes defunct and it amounts to repeal. A sunset clause has to be introduced, so that we can avoid this much of valuable time in future for having a separate Repeal Bill. I understand whenever you bring an amendment by way of a Bill, that amended Act will be there which can be repealed only by a Repeal Act. When you introduce this type of sunset clause in the Bills that will help us in saving a lot of time of this House and we can debate on the people's issues. This is number one.

Two, whenever you bring a Bill, why don't you consult the stakeholders? I have been on the Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice. The Judiciary takes the strain of hearing cases because of an Act which was passed. So why don't you have a judicial impact assessment before a Bill is introduced in the House? Why don't you have consultation with the stakeholders, the judiciary, the advocates and the persons who are going to be affected by the Bill? I will give you an example. When you brought an amendment to Section 138 of the Negotiable Instruments Act, it had a docket explosion. All of a sudden, there were lakhs of cases overnight that the courts had to hear. There was not much infrastructure. Our Chairman, I would say with pride, belongs to our community, namely from legal fraternity. Hon. Chairman knows that when you introduce a Bill and when it becomes an Act, how far it goes to have an impact on the judiciary and on the litigants! This study can be done before a Bill is introduced so that it will not be a surprise for all of them. If you want to bring a Bill which is going to affect a trade or a community or lawyers or other set of people, why don't you give them a hearing? That way, you can interact with them and they will give you suggestions. I am saying this because a lot of amendments are being brought.

Sir, today, I will take up the Arbitration Act. Under Section 34, if you want to set aside an award, the court, which is hearing a matter against an award passed by an arbitrator, has no power to modify an award. It has to only set it aside and send it

back to the arbitrator. Arbitrators are taking years together. Imagine arbitration goes on for five years and the matter comes to the court! The court hears the matter and after another five years, the court is not empowered to modify an award and make it a decree. The power is only to the extent of sending it back to the arbitrator. These types of powers have to be regulated by way of having a discussion with the stakeholders before a Bill is introduced in the Parliament. That is what I would like to say. These repealing Acts are unnecessary. You can stop it by introducing a sunset clause at the beginning itself. That would be my suggestion so that we can avoid wastage of time of this House. This has been followed in foreign countries. So, this can be adopted and we could save time to concentrate more on the people's issues and other issues can be taken up for consideration.

Sir, there is another important issue which I have been raising. The social diversity is not there in the judiciary. When you look at the representation of the number of Judges in the High Courts or the representation of the Supreme Court, social diversity is lacking in the High Courts and the Supreme Court. Please see the information given to the Parliament by the Ministry of Law and Justice. If you see from 2018 to 2023, I am told that about 80 per cent are from upper caste -- I would say, from one community. I don't want to name the community. The rest of 20 per cent are coming from the Backward Classes, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. If you look at the Supreme Court, it is still worse. In fact, Sir, we had even brought a report.

MR. CHAIRMAN: You made your point. You have made your point very emphatically.

SHRI P. WILSON: Sir, I would only make a point. I am grateful to the hon. Chairman. Why don't they consider this representation? What is wrong with a Backward Class person becoming a Judge? Do you think that he can't deliver judgments? I can see two things. Either the collegium has failed to identify a person with merit from other classes or the collegium is not interested in identifying meritorious persons from other classes.

MR. CHAIRMAN: You have made your point.

SHRI P. WILSON: Sir, it is high time that this is considered. Thank you very much for allowing me to speak on this Bill.

MR. CHAIRMAN: Before I call upon the hon. Minister to reply to the discussion, I would say that law-making is a very serious business. We alone are entrusted with law-making. There are two different categories. If Parliament, which is the ultimate architect of the Constitution, makes some change in the Constitution, that is final. There can be no intervention from any agency, be it executive or judiciary. But if there is a legislation, judiciary has a method of intervention by way of judicial review because every legislation has to be in accordance with the constitutional prescriptions. So, things are very categorical. As far as a constitutional provision is concerned, hon. Minister, any intervention with respect to a constitutional provision emanating from Parliament is not acceptable. Parliament is the only reflector of the opinion of the people. This is by way of a structured platform.

People of this country indicate their mindset through the ballot and send their representatives here. I just tell you, we must be quite serious about it. I would just read one provision of the Tenth Schedule of the Indian Constitution and that would surprise all of you. And that is, Tenth Schedule, Clause 6: Decision on questions as to disqualification on ground of defection. But if you go to proviso, "Provided that where the question which has arisen is as to whether the Chairman or the Speaker of a House has become subject to such disqualification, the question shall be referred for the decision of such member of the House as the House may elect in this behalf and his decision shall be final." Now, just reflect. Where is the question of disqualification of Chairman, Rajya Sabha? So, we have to be extremely careful. This was drafted at a time, it was just before we came to power in 1989. So, it is a serious business. I would urge all of you that we are the ultimate custodians of the rights of the people, sovereignty of the people by ensuring that we act diligently, vigilantly, with thorough preparation, make appropriate inputs and do not permit any incursion whatsoever, which is our mandate. And that is the ultimate authority to ensure constitutional compliance and be the architect of the Constitution. Any intervention in this area should be repelled. There was an occasion where we discussed an important Bill. I was looking right, left and centre that someone would reflect as to whether the highest court of the land can make an interim legal arrangement. That is 100 per cent the mandate of this House. I am sure we would engage more seriously when it comes to law-making. Hon. Minister, Shri Arjun Ram Meghwal to reply to the discussion. These reflections were because the hon. Minister is handling the Ministry of Law and Justice.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: धन्यवाद माननीय चेयरमैन सर, आज इस महान सदन ने the Repealing and Amending Bill, 2023 पर चर्चा की। इस बिल पर 8 लोगों ने अपने विचार रखे।

श्री जी.वी.एल नरसिंहा राव जी से लेकर श्री पी. विल्सन तक सबने इस पर अपने विचार रखे। इस पर हमारे डा. मु. तंबी दुरै, श्री महेश जेठमलानी, श्री नरेश बंसल, श्री के.आर. सुरेश रेड्डी, श्री बीडा मस्थान राव यादव और श्री मुजीबुल्ला खान जी ने अपने विचार रखे। सबने अपने सुझाव भी दिए और माना कि वे कानून, जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। सबने इस बिल का समर्थन किया।

सभापति महोदय, यह एक जनरल परसेप्शन है, सिद्धांत है और एक प्रिंसिपल भी है कि मनुष्य की प्राकृतिक मौत हो सकती है, उसका एक्सीडेंट हो सकता है और 70 साल, 80 साल या 100 साल की आयु पूर्ण होने पर प्राकृतिक मौत भी हो सकती है, लेकिन यदि कोई अधिनियम है, तो उसकी प्राकृतिक मौत नहीं हो सकती। उसको अगर किल करना है, तो संसद में ही लाना पड़ेगा। इसलिए हम इन्हें बार-बार यहां लाकर किल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ऐसे बिल्स की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये बार-बार आ रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि एक साथ ले आइए, बार-बार मत लाइए। कुछ लोगों ने sunset clause जैसे सुझाव भी दिए, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह एक प्रक्रिया है। यह नेचुरल डेथ का विषय नहीं है। यह पार्लियामेंट से पास है, कुछ राज्य की विधान सभाओं से पास है, तो संसद में आना ही पड़ेगा। हर बिल में एक्ट का एक नंबर होता है, एक्ट का ईयर भी होता है, कौन-सा लेजिस्लेचर लेकर आया है, कौन-सी विधान सभा ने पास किया है, पार्लियामेंट ने पास किया है, इनका उल्लेख भी होता है। परशोत्तम रुपाला जी बार-बार जिसका जिक्र करते हैं, वह Enacting Formula भी होता है। उसका republican year भी होता है। ये सारी चीज़ें होने से हम सबको एक साथ लेकर आ जाएं, ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी हम इसमें प्रयास कर रहे हैं। आपने sunset clause के बारे में जिक्र किया, उसके संबंध में हम प्रयास कर रहे हैं। जो बिल था, उसमें ऐसे 65 अधिनियम थे, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। एक official amendment के द्वारा ये 11 add हुए हैं, तो जिस बिल की हम चर्चा कर रहे हैं, उसमें टोटल 76 ऐसे कानून हैं। अब तक मोदी जी के आने के बाद - मोदी जी 2014 में शासन में आए, तो उनके आने के बाद हम पहले ही ऐसे 1486 कानूनों को, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, समाप्त कर चुके हैं। 76 कानून, जिसको यह महान सदन पास करेगा, तो टोटल 1562 ऐसे कानून, जिनकी आवश्यकता नहीं है, वे समाप्त हो जाएंगे। नरेन्द्र मोदी जी का एक प्रिंसिपल था - "Minimum Government Maximum Governance", हम इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इससे नागरिकों के Ease of Doing Business और Ease of Living का भी मार्ग आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसे बिल थे, जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है और नागरिकों को तंग करने के अलावा उनका कोई काम नहीं था। जैसे पहले मैंने टेलिग्राम वायर का जिक्र किया कि कोई भी उसको रख नहीं सकता है। अब टेलिग्राम वायर जैसा कोई विषय बचा नहीं है, unlawful activity बची नहीं है। ऐसे ही एक sugarcane का विषय था। हम sugarcane को essential commodity जैसा मानेंगे। अब essential commodity एक्ट आ गया, उसमें चीज़ें define हो गईं, तो उसमें sugarcane का विषय ही नहीं रहा। ऐसे unnecessary एक्ट्स थे, जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं है। अगर हम यूपीए कालखंड की बात करें, तो 2004 से 2014 में एक भी ऐसा एक्ट, जिसके प्रचलन की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी के आने के बाद ऐसे 1562 एक्ट्स समाप्त हो जाएंगे। इसलिए नागरिकों को सुविधा देने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी तेजी से कर रहे हैं। जैसे मेटल कॉरपोरेशन है। अब मेटल को

एक्वायर करना अपराध है। मेटल कॉरपोरेशन के बारे में भी इस बिल में है। अब इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जिनका जिक्र अलग-अलग सदस्यों ने किया है। मैं फिर से कहता हूं कि इसमें अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ का काम होता है। कुछ एक्ट्स स्टेट्स के होते हैं, कहीं पर स्टेट्स की opinion भी ली जाती है। इस सब में टाइम लगता है, लेकिन यह भी एक काम था। मोदी जी से पहले इस पर तेजी से विचार नहीं हुआ। मोदी जी के आने के बाद लगा कि यह भी एक काम है। Unnecessary के एक्ट्स क्यों पड़े हुए हैं? इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जो पंच प्रण हैं, उनके बारे में प्रधान मंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा है कि भारत को विकसित भारत बनाना है। मानव केन्द्रित, Ease of Living - यहां एक विषय यह भी आता है। गुलामी का कोई भी अंश हो, उससे मुक्ति मिलनी चाहिए। ये कानून गुलामी के period के बने हुए हैं, उनसे हमें पंच प्रण के माध्यम से मुक्ति मिल रही है। प्रधान मंत्री जी के पंच प्रण का जो विषय है, उस दिशा में भी हम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक sunset clause के बारे में पी. विल्सन साहब ने कहा। मैं यह कह सकता हूं कि sunset clause is under consideration of the Government and the sunset clause is being considered in consultation with the concerned Ministry and Department. उस पर आगे क्या विषय आएगा, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। फिर मैं कहना चाहता हूं कि यह मोदी सरकार है, जो आगे बढ़ने में विश्वास रखती है, इसलिए हम ऐसे एक्ट्स, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जो ठहरे पानी की तरह हो गए हैं, उन्हें repeal करने का काम आज इस बिल के माध्यम मैं इस महान सदन के सम्मुख लेकर आया हूं। मैंने पहले भी कहा था कि:-

"अगर आगे बढ़ना है, तो बहता पानी बन जाओ,
ठहरा पानी थक जाता है, वह तो अपनी काई से।"

5.00 P.M.

काई तो उसके ऊपर ही होती है। अगर पानी एकदम ठहर गया, तो वह काई से भी थक जाता है। ये ऐसे ही कुछ कानून थे, जो खुद भी थक रहे थे और नागरिकों को भी थका रहे थे। कुछ विषय ज्युडिशियरी से संबंधित भी आए, कुछ टिप्पणी आपने भी की और कुछ जजों की अपॉइंटमेंट को लेकर कि सभी सामाजिक ...

MR. CHAIRMAN: Hon. Minister, we all are proud of our institutions. There are three main organs, the Legislature, the Executive and the Judiciary. The Executive has performed phenomenally. The world has recognized it. We noticed it during G-20. We have seen infrastructure growth of unbelievable dimension. Alleviation of poverty has taken place. So, the Executive is performing very well. These are not political issues, they are above politics. Our Judiciary has a robust infrastructure, known for its independence globally. Our Judiciary, recently, has taken several innovative steps. Even I have directed our Secretariat to get in touch with the Supreme Court Secretariat about translation. Our Judiciary has attained milestones by making

available judgements in the language people understand. Many things have happened. There will always be issues between organizations because we are in a dynamic world. Those issues have to be settled. Some issues may arise from this side, some issues may arise from Executive, some issues may arise from Judiciary. Therefore, this Parliament, this august House, the Upper House is committed to giving highest respect to all the organs because only in togetherness, in tandem, we can achieve success of our democracy to a higher level and take it to 2047 as a developed nation of the world. Therefore, the intent is that if there are differences of opinions, that is just a perception which can be smoothly ironed out. I have no doubt, with a Minister like him, who has seen the Executive -- he has operated Legislature also by virtue of being District Magistrate; he has dual powers-- he is eminently suited and belongs to a category of Dr. Ambedkar. He is the right person, a right platform to smoothen out if there are any rough edges. But we take pride in all our institutions. It is this House that has done justice to one half of humanity by providing reservation to women. It is this House that did away with the temporary provision of Article 370. Historical, epochal events have taken place. So it is from that perspective that hon. Member made some reflections. We have to see it in that perspective. Now the hon. Minister.

श्री अर्जुन राम मेघवालः धन्यवाद सर, आपके जो ऑब्जर्वेशन्स थे, जब कभी हम आने वाले समय में, इस दिशा में consultation process में आगे बढ़ेंगे, तो आपके जो valuable सुझाव हैं, उनको हम उचित प्लेटफार्म पर जरूर उठाएंगे, क्योंकि सब वर्गों का सामाजिक प्रतिनिधित्व Judiciary में होना चाहिए, यह मैं आज observation का सार समझ पा रहा हूं।

सर, जो विषय आपने भाषा का रखा है - एक function में महामहिम राष्ट्रपति जी, Chief Justice of India और हम सब लोग थे। उस वक्त यह भाषा का विषय आया कि ऐसी भाषा में आपके जजमेंट्स होने चाहिए, क्योंकि आप भी तो जनता के लिए ही हो। "We, the people of India" करके Constitution में सबसे पहला वर्ड यही लिखा हुआ है। तीनों अंगों के लिए भी वही सुझाव है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं, नागरिकों के लिए काम करते हैं। अगर ज्युडिशियरी में काम सरल भाषा में होगा, तो सब लोग समझेंगे। मैं समझता हूं कि ज्युडिशियरी ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है और इस दिशा में तेज़ी से काम हुआ है। एक e-court के लिए भी अच्छा काम हुआ है। अगर आपके Secretary-General हैं, तो उनके यहां भी पदनाम Secretary-General हो गया है।

श्री सभापतिः अब वहां भी Secretary-General हो गया है।

श्री अर्जुन राम मेघवालः जी हाँ। अगर अब उसमें बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि काफी सुविधा रहेगी।

सभापति महोदय, एक और दूसरा विषय है। आपने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का नाम लिया। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब का चित्र नहीं था, यानी प्रतिमा नहीं थी। वे लोग अगर 14 अप्रैल या 6 दिसंबर का फंक्शन कहीं मनाते थे, तो उनकी फोटो रखकर मनाते थे। 1923 में, जब डा. बी.आर. अम्बेडकर जी ने पहली बार अपनी वकालत शुरू की थी, तो उनकी वकालत के सौ साल पूरे होने पर, सुप्रीम कोर्ट के मेन लॉन में वकील की ड्रेस में उनकी प्रतिमा लग गई। महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बहुत बड़ा काम किया है और इसके लिए हम आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि चर्चा काफी ठीक हुई है, इसलिए यह जो the Repealing and Amending Bill, 2023 है, जिसके बारे में चर्चा हुई है, मैं आपके माध्यम से उसे सर्वसम्मति से पास कराने का अनुरोध करता हूं। धन्यवाद।

MR. CHAIRMAN: Now, the question is:

"That the Repealing and Amending Bill, 2023, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN: We shall now take up Clause-by-Clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

The First Schedule, the Second Schedule and the Third Schedule were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Arjun Ram Meghwal to move that the Bill be passed.

SHRI ARJUN RAM MEGHWAL: Sir, I move:

That the Bill as passed by Lok Sabha be passed.

The question was put and the motion was adopted.

INFORMATION TO THE HOUSE

MR. CHAIRMAN: Hon. Members, I had indicated to the House that I will come back to the House with respect to an update on the incident. The culprits have been apprehended. The matter is under investigation and it will take its own course.